eNEWS LETTER

June-2016

Jodhpur Development Authority was established under Jodhpur Development Authority Act,2009(Act No. 2 of 2009) under the Department of Urban Development and Housing, Government of Rajasthan for the purposes of planning, coordinating and supervising the proper, orderly and rapid development of the Jodhpur Region and of executing plans, projects and schemes for such development and to provide for matters connected there with.

Composition of Jodhpur Development Authority

A Chairman appointed by the State Government

A Vice-chairman, Jodhpur Development Commissioner, Jodhpur

Principal Secretary to the Government, Urban Governance [Development and Housing] Department or his representative not below the rank of Deputy Secretary

Deputy Housing Commissioner, Rajasthan Housing Board, Jodhpur

Additional Chief Engineer, Public Health Engineering Department, Jodhpur

Additional Chief Engineer, Public Works Department, Jodhpur

District Collector, Jodhpur

Chief Managing Director, Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd., Jodhpur

Chairman/Administrator, Municipal Corporation, Jodhpur

Zila Pramukh of Zila Parishad, Jodhpur

Deputy Town Planner, Jodhpur

Non official members, not exceeding seven to be nominated by the State Government

Contact us

Jodhpur Development Authority
Opposite Railway Hospital
Railway Hospital Road,
Ratanada, Jodhpur(Rajasthan) 342001 India
e-mail-jdajodhpur-rj[at]nic[dot]in
Phone No.- 0291-2612086, 0291-2656355
Fax No. - 0291-2615372

Ratan Lahoti
(I.A.S)
Chairman

"" जोधपुर शहर की जनता द्वारा किये गये अभिनन्दन के लिये आभार व्यक्त करता हूँ। शहर के समग्र विकास हेतु कार्य करना ही मेरा एक मात्र लक्ष्य हैं तथा इसी संकल्प के साथ मैं कार्य करूंगा।
जोधपुर शहर की जनता से अपील हैं कि शहर के विकास में अधिकाधिक भागीदारी निभाए ताकि शहर के विकास हेतु रचनात्मक एवं ठोस कार्य निरन्तर आगे बढे.। ""

Kailashchand Meena
(I.A.S)
Commissioner

"" जोधपुर शहर के विकास में प्राधिकरण अपनी भूमिका निभाने के लिए कृत संकल्पित है। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से जोधपुर के विकास में हम सब मिलकर अपना योगदान देंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ""

Arun Purohit
(R.A.S)
Secretary

"" जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर शहर के समग्र एवं सुनियोजित विकास के लिए दृढ. संकल्प है। मेरा विश्वास है कि इस कार्य को सही दिशा में क्रियान्वित करने के लिए आप सबका अपेक्षित सहयोग मिलता रहेगा। आप हम सब मिलकर विकास के इस सपने को साकार करें। ""

Disclaimer

eNews Letter तैयार करने में सभी तथ्यों को सावधानी से चेक किया गया है। फिर भी मानवीय भूल से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे तथ्यों के आधार पर सुधार कर पुनः प्रदर्शित किया जा सकता है। आपके सुझाव व आपत्ति निम्न पते या ईमेल पर भिजवाए जा सकते है।

दिनांकः– 01/07/2016

पताः–जोधपुर विकास प्राधिकरण,
रेल्वे हॉस्पिटल के सामने, रेल्वे हॉस्पिटल रोड,
रातानाडा, जोधपुर।

ईमेलः– jdajodhpur-rj[at]nic[dot]in

फोनः– 97990–42144
देवेन्द्र गहलोत
एनालिस्ट कम प्रोग्रामर

Concrete Activities

जेडीसी द्वारा राजस्थान सम्पर्क के प्रकरणों में जनसुनवाई सम्पन्न –

जोधपुर विकास प्राधिकरण में गुरुवार को आयुक्त कैलाश चन्द मीना के कक्ष में प्रातः 11 बजे से राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राधिकरण से सम्बन्धित प्रकरणों पर जनसुनवाई हुई। दूरभाष पर पूर्व सूचना देकर आमंत्रित परिवादीगण की जनसुनवाई कर हाथों–हाथ प्रकरणों का निस्तारण किया गया । गुरुवार को हुई जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों, मीडियाकर्मीयों, जनप्रतिनिधियों के समक्ष परिवादीगण को आयुक्त द्वारा तल्लिनता से सुना गया व प्रकरणों में हुई प्रगति के बारे में सम्बन्धित को आवश्यक जानकारी दी गई ।

अतिक्रमण के मामलों को आयुक्त द्वारा गंभीरता से लिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अभियंताओं को उनके क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमणों पर नियमित रूप से निगाह रख रिपोर्ट करने के निर्देश भी प्रदान किए। आयुक्त ने विभिन्न जोन के तहसीलदारों, पटवारी व अतिक्रमण निरीक्षकों की टीम बनाकर आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र करने के निर्देश भी प्रदान किये। आयुक्त ने साफ रुप से निर्देश प्रदान किये कि प्राधिकरण का यह दायित्व है कि प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाली सरकारी भूमियों व योजनाओं में किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दास्त नहीं किया जायेगा। आयुक्त ने अतिक्रमियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु बाईलॉज बनाकर प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश भी प्रदान किये। आयुक्त ने साफ तौर पर कहा प्रत्येक सक्षम अधिकारी का प्राधिकरण की सम्पत्ति पर नज़र रखना उनका नैतिक दायित्व भी है। अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि अंतर्विभागीय दायित्व का निर्वाहन समग्रता से किया जाए, प्राधिकरण कार्यालय में ही अधिकारी पत्रावली को एक दुसरे को मार्क करके अनावश्यक विलम्ब न करते हुए व्यक्तिगत सम्पर्क कर लम्बित व नवीन कार्यों को गति प्रदान करावें। आयुक्त ने अधिकारीगण को टीम भावना से कार्य सम्पादित करने के निर्देश भी प्रदान किये।

अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग योजना व नवीन योजनाओं हेतु भूमि चिन्हित कर समुचित रुप से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये थे लेकिन अभी तक उक्त कार्य में आपसी समन्वय नहीं होने के कारण गति नहीं आयी हैं। आयुक्त ने अधिकारियों को कहा कि जो प्रकरण प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं है उन प्रकरणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित को सूचित किया जावें। आयुक्त ने एक–दो मामलों में सम्बन्धित अभियन्ता व तहसीलदार को परिवादी के साथ हाथों–हाथ जाकर मौका देख कर रिपोर्ट करने के निर्देश भी प्रदान किये। आयुक्त द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों को साफ तौर पर यह निर्देश भी प्रदान किये कि वन विभाग की भूमि पर कोई भी गतिविधि अथवा विकास कार्य बिना सक्षम स्वीकृति के नहीं किया जावें। आयुक्त ने प्राधिकरण की योजनाओं में मूल–भूत सुविधाओं, बिजली, पानी, सड़क सहित सुगम यातायात हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करने के भी निर्देश प्रदान किये। आयुक्त ने आमजन की समस्याओं की नियमित सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण पर भी बल दिया।

Concrete Activities

एक मुश्त लीज जमा कराने पर बकाया ब्याज में शत–प्रतिशत की छूट –

राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल की बकाया लीज राशि के ब्याज में छूट के आदेश जारी किये गये है। सरकार द्वारा उक्त छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को 30 जून 2016 तक आवेदन करने पर ही उक्त छूट का लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार 30 जून तक आवेदन करने पर करने वाले आवेदकों हेतु लीज जमा कराने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर 2016 निर्धारित की गई है।

प्राधिकरण आयुक्त कैलाश चन्द मीना ने बताया कि पूर्व की समस्त बकाया वार्षिक लीज राशि मय चालु वर्ष की लीज राशि जमा कराये जाने पर बकाया लीज के ब्याज में 50 प्रतिशत राशि की छूट दी जायेगी। इसी प्रकार पूर्व की समस्त बकाया एवं आगे के लिए सम्पूर्ण एक मुश्त लीज राशि जमा कराये जाने वाले लीज होल्डर्स को बकाया लीज राशि के ब्याज में शत–प्रतिशत छूट दी जायेगी। प्राधिकरण एसीपी ने बताया कि प्राधिकरण की योजनाओं के लीजधारियों की सूची प्राधिकरण की वेबसाईट www.jodhpurjda.org पर भी उपलब्ध है। आवेदक प्राधिकरण की एकल खिड़की से भी अपनी बकाया लीज की राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

जेडीए निभाएगा जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका –

जोधपुर विकास आयुक्त कैलाश चन्द मीना ने गुरूवार मध्याह्न पश्चात् अपने कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्य रूप से प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों व जन उपयोगी प्रस्तावित विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि विकास कार्य में गुणवत्ता व समयबद्धता का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए। विकास कार्यों में उच्च स्तर की गुणवत्ता को बरकरार रखने व लगातार कार्य की समीक्षा सुनिश्चित करने हेतु अभियन्ताओं को विशेष निर्देश प्रदान किए गये।

आयुक्त ने जल संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के मध्येनजर जोधपुर विकास प्राधिकरण को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। आयुक्त ने बताया कि बारिश के पानी के संधारण हेतु प्राकृतिक व पुराने नदी, तालाबों इत्यादि पर फोकस कर वर्तमान में कम से कम दस ऐसे कार्य हाथ में लिए जाए जिससे प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले निवासियों को अधिकतम लाभान्वित करने के साथ–साथ उक्त जल संरक्षण स्त्रोत पर्यटन को भी बढ़ावा दें।

बैठक में जोधपुर के भीतरी शहर में ग्राउण्ड वाटर का स्तर ऊपर आने पर चर्चा करते हुए आयुक्त ने कहा कि उक्त समस्या शहर से सटे भीतरी क्षेत्रों की है। प्राधिकरण का क्षेत्रफल भौगोलिक रूप से जयपुर विकास प्राधिकरण से भी बडा है। प्राधिकरण के विभिन्न क्षेत्रों जहां पर ग्राउण्ड वाटर की समस्या नहीं है व जनमानस व पशुधन को लाभान्वित करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर बडी आवासीय कॉलोनियों, व्यावसायिक, सरकारी, गैर–सरकारी संस्थाओं आदि को निर्माण की अनुमति के साथ सुविधा क्षेत्रों में नियमानुसार Rainwater Harvesting संरचनाएं बनाए जाने के निर्देश दिए जाने पर भी बल दिया।

Concrete Activities

बैठक में आयुक्त ने कहा कि "जब सब एकजुट होकर मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे तभी आने वाले समय में इसका लाभ सभी को मिल सकेगा।"

आयुक्त ने अभियन्ताओं को शीघ्र ही इस अभियान के अन्तर्गत जल ग्रहण ढांचों की मरम्मत, जीर्णोद्वार, नालों से मिट्टी निकालना व गहरा करना तथा कुओं, तालाबों प्राकृतिक जल सरंक्षण केन्द्रों का जोनवाईज निरीक्षण करते हुए कम से कम दस प्रस्ताव इसी सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए। बैठक में आयुक्त ने कहा कि जल संरक्षण होगा तो भू–जल बढ़ेगा, सूखे नदी–नालों में पानी आएगा और एक रिवर बेसिन से दूसरे रिवर बेसिन में पानी जाएगा जिससे इसका सदुपयोग होगा। भू–जल का दोहन कम होने के साथ ही भू–जल स्तर बढ़ेगा और लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा।

जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक –

जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक शुक्रवार प्रातः 10.00 कैलाश चन्द मीना, जोधपुर विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष, जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में प्राधिकरण स्थित कक्ष में आयोजित हुई।

बैठक में विकास शर्मा, उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय एवं यातायात) जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, अर्जुनसिंह राठौड, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, दलवीरसिंह ढ्ढा, उपायुक्त, नगर निगम, राजेन्द्रसिंह राठौड़, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, मोहनसिह राजपुरोहित, उपायुक्त–दक्षिण, वेद प्रकाश शर्मा, सहायक उपायुक्त–यातायात (पूर्व) जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, अय्यूब खां, सहायक उपायुक्त–यातायात (पश्चिम) जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, अतुल बल रत्नू, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, ओ.पी. गौड, अधीक्षण अभियन्ता (सी.सी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर, के. के. व्यास, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर, चन्द्रवीर चारण, डीपो मैनेजर, राजस्थान राज्य पथ निगम लिमिटेड, जोधपुर आदि अधिकारियों उपस्थित थे।

बैठक में सर्वप्रथम गत बैठक में लिए गये निर्णयों की पुष्टि की गई। तत्पश्चात् बैठक में शहर की सुचारू यातायात व्यवस्था के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। बैठक में उपस्थित श्री विकास शर्मा, उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर ने दाऊजी की होटल तिराहा एवं एम्स तिराहा का यातायात की दृष्टि से सर्वे करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में इस संबंध में विचार विमर्श कर उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात के निर्देशन में अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला परिवहन अधिकारी एवं यातायात पुलिस के अधिकारियों द्वारा संयुक्त सर्वे करवाकर अपनी रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में ऑटो रिक्शा/सिटी बस स्टेण्डों की समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात ने बैठक में अवगत कराया कि कई स्टेण्ड आज ऐसे हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसी प्रकार कई नवीन स्थल जैसे कायलाना के पास माचिया सफारी पार्क, भदवासिया फल सब्जी मण्डी के पास, पावटा सी रोड पर रजवाडा मार्बल गौदाम के आगे आरटीओ कार्यालय की तरफ आदि स्थानों

Concrete Activities

पर ऑटो रिक्शा स्टेण्ड अधिसूचित करने की आवश्यकता है।

बैठक में उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात ने बैठक में अवगत कराया कि अधिकांश अधिसूचित सिटी बस/ऑटो रिक्शा स्टेण्ड पर पर अतिक्रमण पाये जाते हैं जिसके कारण अधिसूचित स्टेण्ड का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है तथा आम नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में बैठक में बाद विचार–विमर्श सर्व सम्मति से ऐसे स्टेण्डों को नो–वेडिंग जोन घोषित करने हेतु आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे सिटी बस/ऑटो रिक्शा स्टेण्ड की सूची व विवरण उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर को जरिये पत्र सूचित किया जावेगा।

शहर में लगेगें नये यातायात सिग्नल एवं संकेत बोर्ड

बैठक में उपस्थित श्री विकास शर्मा, उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर ने अवगत कराया कि पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में ध्वनि निषेध क्षेत्र के बोर्ड लगाये जाने है। उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर ने अपने पत्र के अन्तर्गत ऐसे 26 स्थान अंकित किये है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात के पत्र दिनांक 14 के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित 26 स्थानों पर प्राधिकरण की ओर से यातायात पुलिस के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में संकेत बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में उपस्थित उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर ने अवगत कराया कि हाल ही में खतरनाक पुलिया व तारघर घुमटी के पास यातायात सिग्नल लाईटें लगाये गयी है। तारघर घुमटी पर सबसे ऊपर लगी लाल बती रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 02 से रेलवे ड्राईवरों को भ्रमित करती है, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है। इसके निराकरण हेतु विशेषज्ञ से मौका निरीक्षण कराया जावे तथा बाउण्ड्री वाल पर हॉर्डिंग लगाये जाकर इसका निराकरण किया जा सकता है। इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रथमदृष्टया रेलवे की दीवार है, जिसे ऊंचा किया जाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस संबंध में उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर को रेलवे विभाग को उक्त दीवार ऊंची करने हेतु निवेदन करने हेतु पत्र लिखने का निर्देश प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यदि रेलवे विभाग इस दीवार को ऊंची करने में असमर्थ है तो नियमानुसार रेलवे विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त दीवार को ऊंची करने का कार्य प्राथमिकता से किया जावे ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की आशंका नहीं रहे।

शहर के बस–स्टैण्ड का होगा सौन्दर्यकरण व सुदृढ़ीकरण

बैठक में शहर के बस स्टेण्डों का सौन्दर्यकरण एवं सुदृढ़ीकरण के संबंध में विचार विमर्श किया जाकर यह निर्णय

Concrete Activities

लिया गया कि बस स्टेण्ड वर्तमान में नगर निगम, जोधपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित है। बस स्टेण्ड का सौन्दर्यकरण व सुदृढीकरण का कार्य नगर निगम, जोधपुर द्वारा करवाया जाने का निर्णय लिया गया ।

रोड कट्स व रोड क्रॉसिंग/डिवाईडर पर हुई चर्चा

बैठक में विकास शर्मा ने अवगत कराया कि विभिन्न स्थानों पर नवीन रोड डिवाईडर बनाने व अनावश्यक कट बन्द करवाने तथा सडक डिवाईडर कट को खुलवाने की आवश्यकता है।

यातायात व्यवस्था व जागरूकता हेतु बढ़ेगी आई.ई.सी. गतिविधियां

बैठक में उपस्थित श्री विकास शर्मा, उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर ने अवगत कराया कि आम नागरिकों में यातायात के प्रति जागरूकता लाने की दृष्टि से यातायात पुलिस द्वारा स्कूलों एवं अन्य संस्थाओं में जाकर छात्रों व आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए इसे निर्बाध रूप से जारी रखने एवं और अधिक प्रभावी तरीके से यातायात जागरूकता के लिए कार्य करने हेतु प्रयास करने का निर्णय लिया गया।

गति सीमा के बोर्ड लगाने हेतु स्थानों का हुआ निर्णय

बैठक में उपस्थित विकास शर्मा द्वारा अवगत कराया कि पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों के लिए अलग–अलग गति सीमा की अधिसूचना निर्धारित की जा चुकी है। शहर में वर्तमान में अधिसूचित गति सीमा के बोर्ड नियमानुसार लगाने की आवश्यकता है ताकि आमजन को सड़कों पर वाहनों की गति सीमा से संबंधित जानकारी मिल सके। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से वर्णित स्थलों पर उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा चयनित स्थल पर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा लगाये/स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया। लगाये जाने/स्थापित किये जाने वाले गतिसीमा के बोर्ड का प्रारूप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा दिया जावेगा।

सी.सी. टीवी कैमरे व पब्लिक एड्रेस सिस्टम

बैठक में अवगत कराया कि कृषि मण्डी के पास सी.सी. टीवी कैमरे लगाने की मांग की है। बैठक में उपस्थित अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत भंवरलाल चौधरी ने अवगत कराया कि सीसी टीवी कैमरे लगाने हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है। आगामी एक दो दिवस में उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात के निर्देशानुसार कैमरे लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जावे। साथ ही बैठक में उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात के पत्र पर विचार विमर्श कर फिलहाल तीन मुख्य चौराहे यथा पावटा चौराहा, नई सडक चौराहा एवं जालोरीगेट चौराहा पर प्रायोगिक तौर पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा लगाने का निर्णय लिया गया।

Concrete Activities

पार्किंग स्थल व जेब्रा लाईन

बैठक में 48 स्थानों पर नई जेब्रा लाईन लगाने एवं शहर के विभिन्न यातायात पॉईन्ट्स पर पार्किंग व जेब्रा लाईन आदि लगाने के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने की मांग की है। बैठक में विचार विमर्श कर 48 स्थानों तथा शहर के विभिन्न यातायात पॉईन्ट्स पर पार्किंग व जेब्रा लाईन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से लगाने का निर्णय लिया गया।

नई यातायात घुमटियों की आवश्यकता

बैठक में अवगत कराया कि विभिन्न 7 स्थानों पर नई यातायात घुमटी लगाने पर विचार विमर्श कर सातों स्थानों पर नई यातायात घुमटी उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से लगाने का निर्णय लिया गया। नई यातायात घुमटियों की डिजाईन गर्मी व वर्षा से बचाव आदि को दृष्टिगत रखते हुए उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात से अनुमोदित करवाकर निर्माण करवायी जावेगी।

बरसात के मौसम के मध्यनजर सडकों पर खड्डे व नाला मरम्मत/सफाई के संबंध में हुए निर्णय

बैठक में अवगत कराया कि आगामी वर्षा को मद्देनजर रखते हुए सफाई की मांग की है। बैठक में विचार विमर्श कर खतरनाक पुलिया, कलेक्ट्रेट रोड, रेजीडेन्सी रोड, गौरव पथ, पॉचबत्ती आदि स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर स्थित नालों की सफाई व मरम्मत का कार्य नगर निगम, जोधपुर द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता से करवाने हेतु उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर को आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर को पत्र लिखकर अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित श्री विकास शर्मा द्वारा शहर के सभी प्रमुख चौराहें पर मूत्रालय की स्थायी/अस्थायी मूत्रालय की व्यवस्था नगर निगम द्वारा करवाये जाने की मांग की है ताकि इसका उपयोग आमजन व पुलिसकर्मियों द्वारा किया जा सके। बैठक में उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात के सुझाव पर विचार विमर्श कर शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर मूत्रालय की स्थायी/अस्थायी व्यवस्था नगर निगम द्वारा करवाये जाने हेतु उपायुक्त–मुख्यालय एवं यातायात द्वारा आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर को पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया।

ब्लाईंड कट्स के संबंध में हुआ निर्णय

बैठक में उपस्थित श्री विकास शर्मा ने अवगत कराया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर डिवाईडर बनाकर सुगम यातायात हेतु कट्स दिये गये तथा डिवाईडर पर सौन्दर्यकरण के लिए फुलवारी लगायी गई है, परन्तु उक्त फुलवारी के कारण मुडने वाले वाहनों को सीधा आने वाला वाहन दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण यह ब्लाईंड कट साबित हो रहे है। इसके निराकरण हेतु कट के पास से 10 फीट की दूरी तक इस फुलवारी को साफ करवा दिया जावे ताकि वहां पर स्पष्टदृश्यता बनी रहे तथा कट ब्लाईंड नहीं हो सके।

Concrete Activities

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कट के पास 10 फीट की दूरी बहुत ही कम है। यह दूरी कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे कट के पास कम से कम 10 मीटर तक फुलवारी को साफ करवाया जावे ताकि वहां स्पष्टदृश्यता बनी रहे।

प्राधिकरण द्वारा ट्रेंचलेस तकनीक से सीवरेज प्रणाली बिछाने का कार्य –

शहर की प्रमुख व व्यस्त सडकों पर निर्बाध पूर्वक कार्य सम्पादित करने हेतु प्राधिकरण द्वारा ट्रेंचलेस तकनीक से सीवरेज प्रणाली बिछाने का कार्य भी करवाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत रातानाडा एयरपोर्ट मुख्य सडक, डालीबाई बाईपास मुख्य सडक, जोधपुर बाडमेर मुख्य सडक पर कार्य सम्पादित करवाया जा चुका है एवं वर्तमान में शताब्दी चौराहा पाली रोड पर कार्य प्रगतिरत है।

जोधपुर मास्टर प्लान 2001–2023 के तहत् शहर क्षेत्र मे वर्ष 2023 तक 280 वर्ग कि.मी. क्षेत्र नगर निगम परिधि के तहत आबादी में विकसित होगा। जोधपुर शहर के विस्तार को ध्यान में रखते हुए जो.वि.प्रा. ने जोधपुर के शेष एवं विकसित क्षैत्र में गन्दे पानी की निकासी हेतु विस्तृत सर्वे एवं डिजाइन का कार्य कर रू. 737.44 करोड अनुमानित लागत का सीवरेज मास्टर प्लान तैयार किया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये सीवरेज मास्टर प्लान की डीपीआर को राज्य सरकार (UDH) की 12जी एसएलएससी के द्वारा दिनांक 13.09.2013 को स्वीकृति जारी कर रूपये 607.26 करोड़ की योजना को केन्द्र सरकार के द्वारा यूआईडीएसएसएमटी मद में स्वीकृति शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। MoUD, GoI द्वारा इस सीवरेज मास्टर प्लान के फेज प्रथम राशि रू० 184.24 करोड़ को स्वीकृत कर दिया गया था, लेकिन भारत सरकार की जेएनएनयूआरएम योजना को दिनांक 31.03.2014 पश्चात समाप्त घोषित कर दिये जाने से प्राधिकरण को स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं हो सकी।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत शहर के नव विकसित व वंचित रहे क्षेत्रों में सीवरेज प्रणाली बिछाने का कार्य सीवरेज के स्वीकृत मास्टर प्लान (अनुमानित राशि रू. 737.44 करोड़) के अन्तर्गत सर्वे डिजाईन के आधार पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति उपरान्त स्वयं के मद से सीवरेज प्रणाली बिछाने के कुल 6 पैकेज अनुबन्ध कार्य प्रगतिरत हैं। प्रगतिरत कार्यों को योजनाबद्ध रूप Disposal point तक सम्पादित किया जा रहा हैं जिसमें मुख्य कार्य निम्न है।

जोधपुर शहर व रातानाड़ा क्षेत्र में पूर्व से विधमान सीवरेज प्रणाली का निस्तारण एयरपोर्ट रोड़'– झालामण्ड होते हुए सालावास सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक होता है। प्राधिकरण द्वारा लगभग 6 किलोमीटर लम्बाई में 1600/1200 एम.एम व्यास की ट्रंक सीवर लाईन बिछाकर उपरोक्त क्षेत्र के सीवर को नगर निगम जोधपुर अधीन प्रस्तावित बासनी बेंदा एस.टी.पी तक निस्तारित करना प्रस्तावित है।

Concrete Activities

उक्त ट्रंक सीवर बिछाने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और माह सितम्बर 2016 तक रातानाड़ा चौराहे से सीवर को नई ट्रंक लाईन में प्रवाहित कर बासनी बेंदा एस.टी.पी तक पहुचाना लक्षित है। उक्त कार्य के संपादन के पश्चात् रातानाड़ा–एयरपोर्ट नाले में व्याप्त सीवरेज की गंदगी से निजात मिलेगी।

जोधपुर शहर के नवविकसित ड़िगाडी व शिकारगढ क्षेत्रों में भी सीवरेज प्रणाली बिछाकर उचियाड़ा में प्रस्तावित एस.टी.पी तक निस्तारित किया जा रहा है। इस हेतु ट्रंक सीवर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उचियाड़ा मे प्रस्तावित एस.टी.पी भी प्राधिकरण अन्तर्गत स्वीकृत सीवरेज मास्टर प्लान मे सम्मिलित है जिससे आने वाले वित्तीय वर्षों में सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है।

जोधपुर शहर के झालामण्ड व आस पास के वंचित/नवविकसित क्षेत्रों में एवं प्राधिकरण की विवेक विहार–विजयराजे नगर योजना में भी स्वीकृत मास्टर प्लान अनुरूप सीवरेज प्रणाली बिछाने का कार्य सम्पादित करवाया जा रहा है जिसका निस्तारण विवेक विहार योजना में नदी के पास आरक्षित भूमि में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाकर किया जाना प्रस्तावित है। विवेक विहार में प्रस्तावित एस.टी.पी भी प्राधिकरण अन्तर्गत स्वीकृत सीवरेज मास्टर प्लान मे सम्मिलित है जिससे आने वाले वितिय वर्षो में सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है।

जोधपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र में (शोभावतों की ढाणी, पाल रोड़, डीपीएस स्कूल, सांगरिया फांटा, सालावास रोड़ इत्यादि) व पश्चिमी (सूरसागर, चौपासनी रोड़–बिड़ला स्कूल डाली बाई मन्दिर के मध्य का पाल बाईपास तक का क्षेत्र) में भी सीवरेज प्रणाली बिछाये जाने का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। इस हेतु सालावास एस.टी.पी तक विधमान 1600 एम.एम की मुख्य सीवर से डालीबाई चौराहा तक लगभग 13 किलोमीटर लम्बाई की एक नई ट्रंक लाईन (1400 एम.एम– 400 एम एम व्यास) बिछाई जा रही है। इसके अलावा आस पास के वृहद क्षेत्र को जोड़ने हेतु मुख्य सीवर लाईन बिछाने का कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रों से होने वाले सम्पूर्ण सीवर का सालावास में विधमान एस.टी.पी (100 एम.एलडी) पर किया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार कुल रू. 218 करोड़ कार्यादेश लागत के 477 कि.मी. लम्बाई में सीवर प्रणाली बिछाने के कार्य प्राधिकरण अधीन प्रगतिरत है जिसमें से वर्तमान तक 100.00 करोड़ का व्यय कर लगभग 222 किमी लम्बाई में सीवर प्रणाली का कार्य संपादित हो चुका है। प्रगतिरत सीवरेज प्रणाली कार्यों में शहर के ऐसे बाहरी वंचित क्षेत्र जहां अत्यधिक भूमिगत जल के कारण सोकपिट बनाया जाना सम्भव नहीं हैं भी शामिल हैं। इन कार्यों के सम्पादन से विद्यमान एवं प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेन्ट संयंत्रों तक सीवर परिवहन की वांछित क्षमता की प्राप्ति के साथ वंचित एवं नव विकसित क्षेत्रों में सीवरेज प्रणाली की सुविधा प्रदान करना संभव हो सकेगा जिससे शहर का सेनीटेशन सुविधा का स्तर सुधारना संभव हो सकेगा।

Concrete Activities

अरूण पुरोहित ने जेडीए सचिव का पदभार संभाला –

अरुण पुरोहित ने सोमवार को जोधपुर विकास प्राधिकरण के सचिव पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करते ही प्राधिकरण के अधिकारीगण व कर्मचारियों ने उनसे मुलाकात कर सम्मान प्रकट किया। पुरोहित ने अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जोधपुर के विकास में प्राधिकरण विकास आयुक्त के साथ कन्धें से कन्धा मिलाकर चलना है, इसमें कोई कोर–कसर नहीं होनी चाहिए। पुरोहित के पदभार ग्रहण करते ही कई सस्थांओं के प्रतिनिधि मण्डल, विशिष्ठ व जनसामान्य भी आकर मिले और उनका आभार व हर्ष प्रकट किया।

जेडीए का 800 करोड़ का बजट पारित –

जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक गुरूवार को सम्भागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष रतन लाहोटी की अध्यक्षता में अपराह्न 4:30 बजे प्राधिकरण कार्यालय में शुरू की जाकर सांय 7 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट, वर्तमान विकास कार्यों, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, विद्युतीकरण, पानी, सीवरेज, पार्क, नवीन योजनाओं, वृहत योजनाओं, वृक्षारोपण, शहरी सौन्दर्यकरण, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना, मास्टर प्लान, रिंग रोड़ व अन्य आवश्यक/अतिआवश्यक एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों पर चर्चा की गई।

आज दिनांक 23.06.2016 को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का वर्ष 2016–17 का बजट प्राधिकरण की इस बैठक में 800 करोड़ रूपये की आय तथा इतनी ही राशि का व्यय अनुमानित किया गया है। बैठक सायः 4:30 बजे प्रारम्भ हुई जिसमें जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक, आयुक्त कैलाश चन्द मीना, सचिव अरूण पुरोहित, निदेशक वित्त अतुल बल रतनू, प्राधिकरण के उपायुक्तगण, निदेशकगण, निगम आयुक्त अरूण हसीजा, राजस्थान आवासन मण्डल, पीएचईडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, एनएचए, डिस्कॉम, आईआईटी आदि विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि सभी विभागों को अपने मत–भेद भुलाते हुए परस्पर एक दूसरे के सहयोग से जोधपुर को बेहतरीन व स्मार्टसिटी के रूप में विकसित करने का विजन रखना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा

Concrete Activities

जोधपुर के नवसृजन व विकास के संबंध में बारी–बारी से सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से विचार व प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए कहा कि जोधपुर के आधुनिकीरण, सुदृढ़ीकरण, सुनियोजित यातायात, विभिन्न योजनाओं में मूलभूत सुविधाएँ, सीवरेज का नवीनतम प्रबंधन, बिजली, पानी, सड़क, पार्क, जनसुविधाएँ सहित शहर को पर्यटन व आमजन के लिए हर तरह के सम्भव प्रयास सभी विभागों को मिलकर करने चाहिए।

जोधपुर विकास आयुक्त कैलाश चन्द मीना ने बताया कि अनुमानित आय में सर्वाधिक 667 करोड रूपये भूमि विक्रय से प्राप्त होगी इसके अलावा भूमि रूपान्तरण, लीज, ऋण, शुल्क, शास्तियॉ, किराया आदि से भी आय प्राप्त होगी। कुल व्यय 800 करोड़ रू किया जाऐगा जिसमें से 689 करोड़ रू विकास कार्यों पर व्यय किये जाऐगे। इस बजट में नवीन पहल के अन्तर्गत विवेक विहार में 10 करोड रू की लागत से कन्वेनशन सेन्टर की स्थापना, सर्किट हाऊस से एयरपोर्ट रोड का नवनिर्माण, शहर के प्रमुख स्थालों पर बस स्टॉपों का आधुनिकीकरण, शहर पर प्रवेश करने वाले प्रमुख 6 बाहरी मार्गों पर कलात्मक प्रवेश द्वारों का निर्माण, प्राधिकरण कार्य से भास्कर चौराहा तक प्राधिकरण चौराहा से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय के मार्ग का सौन्दर्यकरण एवं विकास, मण्डलनाथ में केप्टस पार्क की स्थापना, राजीव गांधी नगर में इको रेस्टोरेशन जोन के रूप में विकसित किये जाने के हेतु विकास कार्य करवाये जायेगें। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ रू व्यय किये जायेगे तथा शहर के प्रमुख तीन अस्पतालों में आधार भूत सुविधाओं के लिए प्राधिकरण द्वारा राशि व्यय की जाएगी।

इसके अतिरिक्त बैठक में वर्ष 2015–16 की वास्तविक आय 440 करोड़ रू तथा इसके विरूद्ध किये गये व्यय 342 करोड़ रू के वास्तविक अंको का अनुमोदन भी सर्व सम्मति से किया गया। जानकारों का मानना है कि प्राधिकरण के इस बैठक के बाद जोधपुर शहर विकास के नए आयामों को छूएगा। बैठक में सम्भागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर द्वारा आगामी दिनों में मानसून को देखते हुए सभी सम्बन्धित विभागों को पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई। आईआईटी से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भी बैठक के दौरान शहर का समुचित व सुनियोजित विकास के संबंध में अपना प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया।

Concrete Activities

बैठक में सभी प्रस्तावों पर विस्तार से विचार विमर्श करने के पश्चात् बजट प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किये जाने पर अध्यक्ष महोदय ने समस्त उपस्थित सदस्यगणों/अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

जेडीए कार्यकारी समिति की बैठक सम्पन्न –

जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यकारी समिति की बैठक सोमवार को जोधपुर विकास आयुक्त कैलाश चन्द मीना की अध्यक्षता में अपराह्न 4:00 बजे प्राधिकरण कार्यालय में शुरू की जाकर सांय 5:30 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में अरूण पुरोहित सचिव, रघुनाथ गर्ग एएसपी जेडीए, चन्द्रवीर एआरएम, आरएसआरसीटी, सुमनेश माथुर एसई नगर निगम, लक्ष्मीनारायण शर्मा एडीसीपी पुलिस, मोहनसिंह राजपुरोहित उपायुक्त, रामलाल सियाग एसई जेडीए, अतुल बल रतनू निदेशक वित्त जेडीए, एनएस शेखावत निदेशक विधि जेडीए व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

सर्वप्रथम बैठक में गत बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि सर्वसम्मति से की गई। तत्पश्चात् प्राधिकरण की समस्त प्राप्तियॉ एवं भुगतान (ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन) करने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। ऑन लाईन भुगतान की सुविधा उत्पन्न होने से आमजन को काफी राहत व सुविधा होने के साथ–साथ प्राधिकरण के विभिन्न प्रकार के भुगतान ऑनलाईन सम्भव हो सके इस हेतु प्राधिकरण द्वारा बैंक के माध्यम से पेमेंट गेट वे लिया जाकर कैश मेनेजमेंट सिस्टम व आई स्योर पे के अन्तर्गत प्राधिकरण के पक्ष में रोकड़ जमा करायी जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिससे लेन–देनों का दिन–प्रतिदिनों के आधार पर रियल टाईम रिकॉनस्लिेशन सम्बन्धित बैंक द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिस बैंक से एमओयू किया जाएगा उस बैंक द्वारा इसके अतिरिक्त अन्य आनुषंगिक सेवायें भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इन सेवाओं में रोकड़ एवं चैकों के पिकअप की सुविधा भी शामिल है।

33 केवी जी.एस.एस. सब स्टेशन निर्माण हेतु विद्युत विभाग को भूमि आवंटन पर हुई चर्चा –

मानसरोवर कोलॉनी के रहवासियों द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन पर कोलॉनी में वॉल्टेज की अत्यन्त समस्या होने पर खसरा संख्या 265/1 ग्राम पाल में 33/11 केवी सबस्टेशन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की मांग प्राधिकरण के समक्ष की गई । प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 231 में ओसीएफ की जमीन आरक्षित है। बैठक में आवंटन की सक्षम स्वीकृति नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से लिया जाना का निर्णय लिया गया।

विवेक विहार योजना में विद्युतीकरण सबस्टेशन स्थापना हेतु विद्युत विभाग को तीन 33/11 के.वी. जी.एस.एस. एवं 132/33 केवी जी.एस.एस. निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन पर हुई चर्चा –

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में विधुतीकरण के कार्य हेतु योजना के सेक्टर–सी, ई व जे में जी.एस.एस. हेतु आरक्षित भूमियां 33/11 केवी जी.एस.एस. एवं सेक्टर जे में ओसीएफ हेतु आरक्षित 7908.87 वर्गमीटर भूमि में से

Concrete Activities

5000 वर्गमीटर भूमि 132/33 केवी जी.एस.एस. हेतु प्राधिकरण के अधिशाषी अभियंता (विधुत) द्वारा निःशुल्क विधुत विभाग को आवंटन करने की मांग की गई।

क्रं.स	सेक्टर	भूमि का आरक्षित प्रकार	क्षेत्रफल
1.	सी	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	1432.00 वर्गमीटर
2.	ई	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	1812.00 वर्गमीटर
3.	जे	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	1674.80 वर्गमीटर
4.	जे	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	7908.87 वर्गमीटर

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अर्न्तगत ग्राम तनावडा में बनेगें 592 आवासगृह :–

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत राजस्व गांव तनावड़ा में 400 ई. डब्ल्यू.एस एवं 192 एल.आई.जी. के अन्तर्गत कुल 592 आवास गृह निमार्ण हेतु दिनांक 24.11.2015 को अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) निविदा सूचना सं. 34/15–16 जारी की गई थी। उक्त योजना हेतु जोधपुर विकास प्रधिकरण की निविदा स्वीकृत कमेटी द्वारा सर्वसहमति से प्राप्त दरों का अनुमोदन कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु राज्य सरकार से समुचित दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके है। प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अर्न्तगत कमजोर आय वर्ग व अल्पआय वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न स्थानों पर नवीन प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ली नेड कदमखण्डी व विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन पर हुई चर्चा :–

विकास अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर मुख्य मण्डोर द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र 'स' प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ली नेड कदमखण्डी बड़ली खसरा न0 88 में 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का अनुरोध प्राधिकरण को किया गया था।

नवीन आवंटन नीति 2015 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु संभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान होने के कारण बैठक में यथोचित प्रक्रिया अपनाते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

इसी प्रकार बैठक में खसरा नं. 141 (मीन) रिडमल नगर में चिकित्सालय एवं बहुउद्धेश्य सेवा प्रकल्प के लिए जमीन आवंटन, पेरोनमा हेतु भूमि आवंटन, उच्च जलाशय हेतु भूमि आवंटन, रामकृष्ण सेवाश्रम को भूमि आवंटन, इंस्टीट्यूट सेकेट्रीज ऑफ इण्डिया को भूमि आवंटन, उच्च जलाशय का निर्माण हेतु डालीबाई मंदिर जैसलमेर बाईपास रोड पर भूमि आवंटन, विवेक विहार योजना में ग्राम पंचायत के लिए भूमि आवंटन, सरदार पटेल शिक्षण संस्थान भूमि आवंटन के संबंध में बैठक में चर्चा की गई।

Concrete Activities

बैठक में विभिन्न सर्वे कम्पनियों द्वारा किये गये सर्वे कार्यों, प्राधिकरण क्षेत्र में जिला परिषद/ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने, प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के 395 राजस्व ग्राम में प्राधिकरण के विरूद्ध लम्बित प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करने, पब्लिक वर्क्स कमेटी का गठन करने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई।